भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 180

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

पीएम इंटर्नशिप योजना

180. सुश्री सयानी घोषः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रारम्भ से लेकर इसके अंतर्गत प्रत्येक चरण में आवेदन किए गए, चयनित तथा इंटर्नशिप पूरी किये बिना छोड़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या चरणवार और वर्षवार कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और संवितरण के लिए लंबित है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त योजना में छात्रों द्वारा स्वीकृति और भागीदारी की दर कम देखी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कौशल विकास, रोजगार और क्षमता निर्माण के संदर्भ में उक्त योजना की प्रभावशीलता और परिणामों की कोई समीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इस योजना को और अधिक आकर्षक और छात्रों के लिए लाभप्रद बनाने के लिए इसके डिजाइन और कार्यान्वयन में कोई परिवर्तन या सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ग): प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को स्कीम की एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है, जिसका लक्ष्य युवाओं को एक वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के पहले राउंड में, साझेदार कंपनियों ने देश भर में पीएमआईएस पोर्टल पर 1.27 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। इसके प्रति करीब 1.81 लाख अभ्यर्थियों से 6.21 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। साझेदार कंपनियों ने 60,000

से अधिक अभ्यर्थियों को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए और 8700 से अधिक प्रस्ताव स्वीकार किए गए। 26.11.2025 तक, पहले राउंड के 4565 अभ्यर्थियों ने इंटर्नशिप पूरी किए बिना ही छोड़ दिया है।

9 जनवरी, 2025 को शुरू हुए पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे राउंड में, साझेदार कंपनियों ने देश भर में 1.18 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसर (पिछले राउंड के नए और संपादित अपूरित अवसर) पोस्ट किए हैं। इस राउंड में 2.14 लाख से अधिक आवेदकों से 4.55 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 26.11.2025 तक, साझेदार कंपनियों ने युवाओं को 83000 से अधिक प्रस्ताव दिए हैं और 24600 से अधिक प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। 26.11.2025 तक, दूसरे राउंड के 2053 अभ्यर्थियों ने इंटर्नशिप पूरी किए बिना ही छोड़ दिया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए समवर्ती मूल्यांकन और फीडबैक सर्वेक्षण के आधार पर, कॉल सेंटर द्वारा अभ्यर्थियों को किए गए आउटबाउंड कॉल और अभ्यर्थियों, उद्योग और उद्योग संघों और राज्य सरकारों जैसे विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, कम स्वीकृति/ज्वाइनिंग के कुछ दृष्टिगत कारण नीचे दिए गए हैं:

- स्थान एक महत्वपूर्ण विचार है और अभ्यर्थियों द्वारा इंगित आदर्श यात्रा दूरी 5-10 किमी के बीच है।
- 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि सामान्य कौशल कार्यक्रमों की तुलना में अधिक है।
- कुछ अभ्यर्थियों को प्रस्तावित भूमिकाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है।

(ख): वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में, पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय को 2000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य वाली पीएम इंटर्नशिप स्कीम की पायलट प्रोजेक्ट के लिए 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमान 380 करोड़ रुपये आंका गया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10831.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

30.09.2025 तक पीएम इंटर्नशिप स्कीम की पायलट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 73.72 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(घ): पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति को ऐसे कौशल पर वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करे जिसमें कंपनी सीधे तौर पर शामिल हो। यह युवाओं को अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को कम करके उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

पायलट प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिणामों की ट्रैकिंग करने के साथ-साथ पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक समवर्ती

निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम (एमईएल) ढांचा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) स्कीम के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग, राज्य सरकारों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि से प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है क्योंकि अभी कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) इस स्कीम के संवर्धन और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय कार्यक्रम की दृश्यता बढ़ाने और राज्यों में लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन और ऑन-ग्राउंड दोनों मोड में कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रचार अभियानों सहित व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

पायलट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण चरण है जिसने बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले अवधारणाओं, रणनीतियों और प्रणालियों के परीक्षण की अनुमति दी है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का बड़े पैमाने पर शुरू करना पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान हितधारकों के परामर्श और परिणामों के मूल्यांकन से प्राप्त फीडबैक पर आधारित होगा।

*****